एसोचैम का अनुमान, आंतरिक मांग से देश की वृद्धि दर को मिलेगी मजबूती

वैश्विक संकट के बावजूद भी भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में ऊंची बनी रहेगी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

भारत के प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक संकटों के चलते आपूर्ति श्रृंखलाओं के व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मंद हो सकती है पर भारत आंतरिक उपभोग और निवेश मांग की बदौलत अगले वित्त वर्ष 2026-27 सात प्रतिशत से ऊपर की तेज गति से वृद्धि की राह पर बना रहेगा।

एसोचैम का मानना है कि 2026 में वैश्विक वृद्धि दर नरम पड़ कर 3 प्रतिशत से नीचे रह सकती है। संगठन ने आगाह किया है कि चूँकि रुपये के मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है, इसलिए घरेलू बाजार में एलपीजी सिलेंडरों जैसे कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा की कीमतें भी बढ़ी हैं और इसका असर आने वाले समय में महंगाई के रुझानों पर देखने को मिलेगा। उद्योग मंडल ने गुरूवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पश्चिम एशिया युद्ध के असर को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम असरदार और सही समय पर हैं। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के. मिंडा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी में 7.6 प्रतिशतकी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

मिंडा ने कहा कि पिछले कई सालों से सुधारों के ज़रिए सरकार का मज़बूत समर्थन बिज़नेस के भरोसे को बढ़ाता है। घरेलू खपत का रुझान कई सालों के सबसे ऊँचे स्तर पर है, जिसे कर व्यवस्था में सुधार और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) में किए गए साहसी सुधारों से समर्थन मिला है, और निवेश भी उसी रफ़्तार से बढ़ रहा है। श्री मिंडा ने कहा, 'आगे उम्मीद है कि भारत की वृद्धि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में सात प्रतिशत से ऊपर बना रहेगा, जबकि ग्लोबल ग्रोथ के तीन प्रतिशत से नीचे गिरने का डर है।'

एसोचैम का कहना है कि 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगभग 7.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है, और आने वाले वित्त वर्ष, 2026-27 में 7 प्रतिशत से ज़्यादा की वृद्धि की उम्मीद है भू-राजनीतिक और अमेरिका में ऊंचे शुल्क से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, भारत की वृद्धि दर पिछले तीन सालों में सात प्रतिशत से ज़्यादा की रही है। फरवरी 2026 के महीने में भारत का विनिर्माण क्षेत्र संबंधी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 56.9 और सेवा क्षेत्र पीएमआई 58.1 पर रहा जो दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका , चीन और जर्मनी) में सबसे ज़्यादा रहे।

निर्यात में अप्रैल से फरवरी 2025-26 के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह बढ़कर 791 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रत्न और आभूषण, तथा कृषि उत्पादों से एक्सपोर्ट को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। भारत के पास विकसित, उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपने व्यापार को विविध बनाने के कई अवसर मौजूद हैं।

एसोचैम ने कहा है कि भारत के रत्न और आभूषण क्षेत्र ने पश्चिम एशिया को लगभग 8.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जिसमें दुबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। लॉजिस्टिक्स में आने वाली बाधाओं के कारण शिपमेंट में देरी हो सकती है, जिससे व्यापारियों और निर्माताओं की लागत बढ़ सकती है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों का भारत के फार्मा निर्यात में लगभग 5.6 प्रतिशत हिस्सा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर

पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाली बड़ी रुकावटों के कारण विश्व के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 3 प्रतिशत से भी नीचे गिर सकती है। पश्चिम एशिया तेल, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरकों और एल्युमीनियम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों का असर ऊर्जा, ऑटोमोटिव, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, तथा कृषि और खाद्य आपूर्ति ृंखलाओं पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसका वैश्विक जीडीपी में लगभग 11 प्रतिशत योगदान है, और इसका असर वैश्विक विकास पर भी पड़ेगा। अनुमान है कि कुल मिलाकर, अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है।

देश के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की वृद्धि दर 9 प्रतिशत रही

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

देश का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र वार्षिक आधार पर लगभग नौ प्रतिशत की दर से मजबूत वृद्धि दर्ज हासिल कर रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार यह वृद्धि बढ़ती जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण तक बेहतर पहुंच और चिकित्सा खर्चों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

पॉलिसीधारकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों के प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित की है। आईआरडीएआई द्वारा कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन एक घंटे के भीतर और अंतिम स्वीकृति - तीन घंटे के भीतर किए जाने के निर्देश हैं। इन समय-सीमाओं का उद्देश्य देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को समय पर चिकित्सा देखभाल मिल सके ।

आईआरडीएआई के 2024 के नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों के आधार पर उचित रूप से किया जाए और वे व्यवहार्य और मूल्य-संचालित बने रहें, साथ ही नियुक्त बीमांकिक द्वारा विश्वसनीय डेटा और ग्राहक प्रतिक्रिया का उपयोग करके समीक्षा की जाए।

दावों का निपटान 87.50 प्रतिशत था

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में दावों की संख्या के आधार पर निपटाना क्रमशः 85.66 प्रतिशत, 82.46 प्रतिशत और 87.50 प्रतिशत था। विज्ञप्ति में आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल के हवाले से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित 1,37,361 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1,27,755 (93 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही कर दिया गया।

चांदी की कीमत में 14,000 रुपए की गिरावट दर्ज

नई दिल्ली, आरएनएन। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते दबाव और मजबूत अमेरिकी डॉलर के चलते घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आज राम नवमी के दिन यानी गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शाम 5 बजे ट्रेडिंग शुरू होते ही सोने की कीमतों में करीब 2.43 प्रतिशत करीब 3064 रुपये की गिरावट देखने को मिली, जिससे इसका भाव गिरकर लगभग 1,40,830 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमतों में इससे भी ज्यादा कमजोरी रही और यह लगभग 5.88 प्रतिशत यानी 14,000 रुपये तक फिसलकर 2,24,605 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में आज कमजोरी देखने को मिली। कॉमेक्स पर स्पॉट गोल्ड करीब 2.63 प्रतिशत गिरकर 4,432 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया। बाजार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती रही, जो गुरुवार को 94 के स्तर के ऊपर बना रहा। डॉलर के मजबूत होने से सोना महंगा हो जाता है। वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

ओला इलेक्ट्रिक अपने ग्राहकों के लिए शुरू करने जा रही है एंड आईसीई एज अभियान

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

ओला इलेक्ट्रिक ने गुरुवार को 'एंड आईसीई एज' अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को तेजी से बढ़ावा देना है। कंपनी ने बताया कि इस अभियान के तहत वह अपने एस1 एक्स (2 किलोवाट घंटा) और रोडस्टर एक्स (2.5 किलोवाट घंटा) मॉडल की शुरुआती कीमत 49,999 रुपये रख रही है। इसके साथ ही पूरे उत्पाद समूह पर 50,000 रुपये तक के लाभ भी दिए जा रहे हैं, जो 31 मार्च तक मान्य होंगे। कंपनी का कहना है कि इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहन आम लोगों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बनेंगे, खासकर ऐसे समय में जब ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

इलेक्ट्रिक वाहन 49,999 रु. से उपलब्ध

आठ साल की दी जा रही है ग्राहकों को विस्तारित वारंटी

कंपनी ने ग्राहकों के लिए सेवा से जुड़ी कई सुविधाएं भी दी हैं, जिनमें तय समय के भीतर सेवा, खरीद वापसी गारंटी और लंबी अवधि की वारंटी शामिल है। यदि सेवा में देरी होती है तो ग्राहकों को मुफ्त टैक्सी सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि उसके सभी एस1 स्कूटर और रोडस्टर मोटरसाइकिल पर अब आठ साल की विस्तारित वारंटी दी जा रही है, जिससे ग्राहकों को लंबे समय तक भरोसा और सुविधा मिल सके।

इंडसइंड बैंक ने पेश किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम

मुंबई, आरएनएन। इंडसइंड बैंक ने गुरुवार को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पेश की, जिसके तहत ग्राहक पुनर्निवेश तक दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को जमा रख सकते हैं और इस दौरान आयकर कानून के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। बैंक की ओर से बताया गया है कि यह योजना पूंजीगत लाभ को पुनर्निवेश तक सुरक्षित और नियमों के अनुरूप रखने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे ग्राहक निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर सोच-समझकर उस पूंजी को दोबारा निवेश करने के बारे में निर्णय ले सकेंगे। यह योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से अनुमति मिलने के बाद पेश की गयी है। बोर्ड ने इंडसइंड बैंक को पूंजीगत लाभ योजना, 1988 के अंतर्गत जमा स्वीकार करने की अनुमति दी है।

सरसों के दाम में सुधार से तेल तिलहन में रही मजबूती

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

किसानों की ओर से कम आवक और बड़ी तेल मिलों द्वारा सरसों के दाम 200-300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाये जाने के बाद सरसों तेल-तिलहन कीमतों में आई तेजी के असर से देश के तेल-तिलहन बाजार में अधिकांश तेल-तिलहनों के दाम मजबूत हो गये।

सामान्य कामकाज के बीच मूंगफली तेल-तिलहन के भाव स्थिर रहे। मलेशिया एक्सचेंज में 3.30 बजे लगभग 1.75 प्रतिशत की तेजी थी। शिकॉगो एक्सचेंज में लगभग 2.5 प्रतिशत की तेजी थी और फिलहाल भी यहां सुधार जारी है। बाजार सूत्रों के मुताबिक सरसों की आवक 10 लाख बोरी से भी घटकर लगभग आठ लाख बोरी रह गई है।

जबकि सूरजमुखी, सोयाबीन, पामोलीन से सस्ता होने की वजह से सरसों तेल की मांग बढ़ रही है। आयातित खाद्य तेलों के मुकाबले सरसों का दाम 5-7 रुपये किलो सस्ता है। सरसों की तेजी का असर और 'इन तेलों के दाम विदेशों में भी मजबूत होने के परिणामस्वरूप सोयाबीन तेल-तिलहन, पाम-पामोलीन और बिनौला तेल के दाम में भी मजबूती रही।

म्यूचुअल फंड्स हाउसेज रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड्स ग्राहकों को पेश करते रहेंगे

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, आरएनएन। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड्स ऑफर करते रहेंगे। सेबी ने इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन, सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स के मामले में कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इससे पहले 26 फरवरी को इश्यू सर्कुलर के जरिए रेगुलेटर ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद कुछ चिंता जताई गई थी। सेबी ने अब स्पष्ट किया है कि अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी चिल्ड्रेंस फंड जारी रखने का फैसला लेती है तो वह 20 साल की अवधि वाला लाइफ साइकिल फंड लॉन्च नहीं कर सकेगी। इसी तरह अगर कोई एएमसी रिटायरमेंट फंड को जारी रखना चाहती है तो वह 30 साल की अवधि वाला लाइफ साइकिल फंड लॉन्च नहीं कर सकेगी। अगर कोई एएमसी रिटायरमेंट और चिल्ड्रेन फंड दोनों जारी रखना चाहती है तो वह 20 साल और 30 साल वाले लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है कि वह सिर्फ 5, 10,15 और 25 साल वाले लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकेगी। कोई एएमसी अगर रिटायरमेंट और चिल्ड्रेंस फंड जारी नहीं रखना चाहती है तो वह सभी छह तरह के लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकेगी।

सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होने पर इंडस्ट्री ने जताई थी चिंता

जानकारों के मुताबिक एंफी रिटायरमेंट और चिल्ड्रेंस फंड बंद करने के रेगुलेटर के फैसले के बारे में सेबी को एक रिप्रजेंटेशन देगा। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने भी एक बयान में कहा था कि वह इंडस्ट्री की चिंता पर विचार कर रहे हैं। एंफी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है।

जियो फाइनेंशियल व एलियांज का साझा रीइंश्योरेंस कारोबार शुरू

● मुंबई / राज न्यूज नेटवर्क

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड और एलियांज़ ग्रुप के संयुक्त उद्यम एलियांज़ जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड ने भारत में अपना कारोबार शुरू कर दिया है।

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कंपनी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) से गत 12 मार्च को अंतिम नियामकीय मंजूरी मिली थी। मुंबई स्थित यह संयुक्त उद्यम जियो फाइनेंशियल की स्थानीय पहुंच और डिजिटल नेटवर्क को एलियांज़ की वैश्विक अंडरराइटिंग विशेषज्ञता के साथ जोड़कर बीमा कंपनियों को जोखिम प्रबंधन क्षमता उपलब्ध कराएगा। जियो फाइनेंशियल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हितेश सेठिया ने कहा कि यह एलियांज़ के साथ व्यापक बीमा साझेदारी की दिशा में पहला कदम है। एलियांज़ के बोर्ड सदस्य क्रिस टाउनसेंड ने कहा कि साझा उद्यम भारत के बीमा बाजार के लिए दीर्घकालिक रीइंश्योरेंस समाधान विकसित करेगी।कंपनी की अगुवाई सोनिया रावल करेंगी, जिन्हें एलियांज़ जियो री का सीईओ नियुक्त किया गया है।

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र जबलपुर भवन नामांतरण/ हस्तांतरण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुभाष नगर महाराजपुर में भवन क्रमांक एल.आई.जी.ई. एल.-109 श्री मनीष कुमार पटेल पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल के नाम आवंटित है। जिसका विक्रय विलेख दिनाँक 27.04.2022 को हो चुका है। आवंटी श्री मनीष कुमार पटेल पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल की मृत्यु दिनांक 30.07.2022 को हो गई है। आवंटी की पत्नि श्रीमति प्रभा पटेल ने नामिनेशन आधार पर उक्त संपत्ति का नामांतरण स्वयं के नाम करने हेतु आवेदन संलग्न दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत किये हैं उसके आधार पर संपत्ति के नामांतरण की कार्यवाही इस कार्यालय में प्रचलन में है यदि किसी व्यक्ति / संस्था को उक्त भवन / भूखण्ड के हस्तांतरण / नामांतरण बाबत् आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने से 15 दिवस के अंदर लिखित एवं वैद्य आपत्ति सप्रमाण स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सुभाष नगर महाराजपुर में भवन कमांक एल.आई.जी.ई.एल.-109 श्री मनीष कुमार पटेल पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल के नाम हस्तांतरण / नामांतरण की कार्यवाही की जावेगी एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति / दावा मान्य नही होगा।

संपदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, प्रक्षेत्र जबलपुर

भारत पीईटी 760 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी

नई दिल्ली, आरएनएन। सामान पैक करने के डिब्बे और बोतलें बनाने वाली कंपनी भारत पीईटी लिमिटेड ने पहला आईपीओ लाकर 760 करोड़ रुपये जुटाने सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं। जमा किए गए 'मसौदा दस्तावेजों' के अनुसार, इस सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत कंपनी 120 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16/04/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
सतना, रिवारोडआदर्श नक्षर, 131840700018627, 9873,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

मांग वृद्धि | पहली तिमाही में सालाना आधार पर हुआ 15 प्रतिशत का इजाफा

भारतीय ऑफिस मार्केट की मांग में मजबूत बढ़ोतरी

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के शीर्ष सात शहरों में ऑफिस मार्केट ने वर्ष 2026 की शुरुआत मजबूत रफ्तार के साथ की है। पहली तिमाही में 183 लाख वर्ग फुट की लीजिंग दर्ज की गई, जो सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों से बढ़ती मांग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विस्तार ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद इस गति को बनाए रखा है।

बेंगलूरु और हैदराबाद ने मिलकर कुल तिमाही लीजिंग का लगभग आधा हिस्सा यानी 87 लाख वर्ग फुट योगदान दिया। वहीं मुंबई, पुणे, दिल्ली-एनसीआर और चेन्नई जैसे शहरों में ग्रेड-ए स्पेस की मांग मजबूत रही, जहां प्रत्येक शहर में 20 से 30 लाख वर्ग फुट के बीच लीजिंग हुई। खास बात यह रही कि हैदराबाद और पुणे में ऑफिस स्पेस की मांग सालाना आधार पर दोगुने से अधिक बढ़ी। बाजार के जानकारों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शीर्ष सात बाजारों में 183 लाख वर्ग फुट ग्रेड-ए स्पेस की लीजिंग भारत के ऑफिस बाजार की मजबूती को दर्शाती है। कुल मांग में जीसीसीएस का योगदान लगभग आधा रहा।

भले ही वैश्विक चुनौतियां प्रोजेक्ट पूर्णता की समय-सीमा को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मांग का परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। दीर्घकालिक जीसीसी विस्तार, विविध ऑक्युपायर बेस, फ्लेक्स स्पेस की बढ़ती पेशकश और उच्च गुणवत्ता वाले एसेट्स की बढ़ती पसंद के कारण भारतीय ऑफिस बाजार एशिया-प्रशांत यानी एपीएसी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल रहेगा।

वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नई आपूर्ति में 19 प्रतिशत की वृद्धि

शीर्ष सात शहरों में नई आपूर्ति 118 लाख वर्ग फुट रही, जो सालाना आधार पर 19 प्रतिशत अधिक है। कुल आपूर्ति में 47 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बेंगलूरु ने सबसे अधिक योगदान दिया, जबकि दिल्ली-एनसीआर 17 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चेन्नई और मुंबई में भी 15-15 लाख वर्ग फुट की आपूर्ति हुई। हैदराबाद और कोलकाता में इस तिमाही नई आपूर्ति ना के बराबर रही।

टेक्नोलॉजी कंपनियों की 36 प्रतिशत हिस्सेदारी

2026 की पहली तिमाही में पारंपरिक ऑफिस स्पेस में 144 लाख वर्ग फुट की लीजिंग हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी और बीएफएसआई सेक्टर ने प्रमुख भूमिका निभाई। इन दोनों सेक्टरों ने मिलकर 95 लाख वर्ग फुट यानी कुल पारंपरिक मांग का लगभग दो-तिहाई हिस्सा लिया। बीएफएसआई की मांग में बेंगलूरु और मुंबई अग्रणी रहे, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों की मांग का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बेंगलूरु और हैदराबाद से आया। फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटरों की लीजिंग में भी 77 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज हुई और यह करीब 40 लाख वर्ग फुट रही। दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद ने मिलकर फ्लेक्स स्पेस लीजिंग का 45 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लिया। कोलकाता और दिल्ली-एनसीआर में कुल तिमाही लीजिंग का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा फ्लेक्स ऑपरेटरों द्वारा लिया गया। हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में फ्लेक्स ऑपरेटरों का योगदान करीब एक-चौथाई रहा।

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर म.प्र.

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	2026_UAD_495023_1 Pro-1025 26/03/2026	संभाग क्रमांक 13 के अंतर्गत स्थित गोलबाजार क्षेत्र के चारों ओर चेम्बरों को लगाने का कार्य।	03 माह 4.21/-	2000/- 4210	10/04/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम,
जबलपुर